इलाज के साथ-साथ अस्पताल के सिस्टम को मजबूत करना भी जरूरी है- डॉ. राहुल

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 47 | मूल्य 05 रुपये | 12-18 अप्रैल, 2026

चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का सख्त एक्शन प्लान

टोल प्लाजा पर नगद भुगतान खत्म

'अब दिल्ली दूर नहीं'

वर्ष 15 | अंक 47

दिव्य हिमगिरि

12-18 अप्रैल, 2026

संपादक
डॉ. कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

संवाददाता
पूनम आर्या

विज्ञापन
सुनील सेमवाल

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*
*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

युद्धविराम के बाद महंगाई का नया दौर

अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शांति की राह खुलने से एक नई उम्मीद जगी है। एक माह से अधिक समय तक वार-पलटवार के बाद आखिरकार दोनों पक्ष दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि शुक्रवार से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच समझौते को लेकर वार्ता शुरू हो सकती है। इस फैसले से दुनिया के उन देशों को भी फिलहाल राहत महसूस हो रही है, जिनका इस युद्ध से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं हैं, लेकिन होर्मुज जलमार्ग बाधित होने से उनके यहां तेल और गैस का संकट पैदा हो गया है। युद्धविराम के एलान का तात्कालिक असर यह हुआ कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के बढ़े दामों में अठारह फीसद की गिरावट दर्ज की गई। इससे निश्चित तौर पर तेल और गैस की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, लेकिन सवाल है कि क्या युद्धविराम स्थायी शांति में तब्दील हो पाएगा? यह प्रश्न इसलिए अहम है, क्योंकि खबरों के मुताबिक ईरान ने अपने प्रस्ताव में जो शर्तें रखी हैं, उन पर आम सहमति कायम करना आसान नहीं होगा। गौरतलब है कि अमेरिका और इजराइल की ओर से 28 फरवरी को ईरान पर हमले के साथ ही युद्ध का बिगुल बज गया था। इसका असर सिर्फ युद्ध में शामिल पक्षों तक ही सीमित नहीं रहा। खाड़ी देशों को जहां ईरान के मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ा, वहीं भारत समेत कई अन्य देशों में तेल एवं गैस का संकट खड़ा हो गया। ईरान ने रणनीति के तहत हार्मुज जलमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वैश्विक आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुई। इस कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में उछाल से कई देशों में पेट्रोल-डीजल, एलपीजी और विमान ईंधन की कीमतें बढ़ गईं। अब दो सप्ताह की युद्धविराम की घोषणा से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी हालात सामान्य रह पाएंगे या नहीं, इस संबंध में अभी अनिश्चितता बरकरार है। ऐसा इसलिए, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से बातचीत की शर्तों को लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। समझौता वार्ता में किस स्तर के प्रतिनिधि शामिल होंगे इसका खुलासा भी अभी नहीं किया गया है। क्या अमेरिका, ईरान की इस शर्त को स्वीकार करेगा, यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि इससे पहले अमेरिका की ओर से दिए गए समझौता प्रस्ताव को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया था। अब जिस प्रस्ताव पर युद्धविराम को लेकर सहमति बनी है, वह ईरान की ओर से पेश किया गया है। खबरों के मुताबिक, ईरान ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि उसे यूरेनियम संवर्धन जारी रखने की छूट दी जाए, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए अहम है। जबकि, अमेरिका और इजराइल के हमले के पीछे प्रमुख कारण यही था कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका, ईरान की इस शर्त को स्वीकार करेगा। खबरों में कहा गया है कि ईरान ने क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी, प्रतिबंधों को हटाना और उसकी जब्त संपत्तियों को वापस सौंपने की शर्त भी रखी है। यही नहीं, ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को इसी शर्त पर खोलने की बात कही है कि वह वहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेगा और इस राशि का इस्तेमाल युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई में किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ, तो इसका असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ेगा। अब देखना होगा कि अमेरिका, ईरान की इन शर्तों को मंजूर करता है या फिर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी।

डॉ. कुँवर राज अस्थाना

इलाज के साथ-साथ अस्पताल के सिस्टम को मजबूत करना भी जरूरी है- डॉ. राहुल

डॉ. राहुल वार्ष्णेय
MBBS, MD, MHA
निदेशक (चिकित्सा सेवाएँ)
ऑल्ट्रस हेल्थकेयर, देहरादून

ऑल्ट्रस हेल्थकेयर, देहरादून के निदेशक डॉ. राहुल वार्ष्णेय स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता और सिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे है। दिव्य हिमगिरी के लिए लोकेश राज अस्थाना की डॉ. राहुल वार्ष्णेय से उनके प्रोफेशनल सफर और नेतृत्व दृष्टिकोण पर विस्तृत बातचीत हुई। पेश है बातचीत के अंश-

आप अपने बारे में बताएँ।
मैं एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ और लंबे समय से क्लिनिकल प्रैक्टिस से जुडा रहा हूँ। इसके साथ ही अस्पतालों की कार्यप्रणाली और गुणवत्ता सुधार की दिशा में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं ऑल्ट्रस हेल्थकेयर, देहरादून में निदेशक के रूप में कार्यरत हूँ। ऑल्ट्रस हेल्थकेयर महिलाओं और बच्चों की देखभाल के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र है जहां प्रसूति, शिशु चिकित्सा एवं सर्जरी के साथ-साथ आईवीएफ, दूरबीन सर्जरी, हड्डी रोग, क्रिटिकल केयर और अन्य आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध है।

चिकित्सा क्षेत्र को आपने अपने करियर के रूप में क्यों चुना?
शुरूआत में ऐसा कोई स्पष्ट कारण नहीं था। मैंने इंजीनियरिंग और मैडिकल, दोनो परीक्षाएँ पास की थी और मन कहीं न कहीं इंजीनियरिंग की ओर झुक रहा था। लेकिन समय के साथ महसूस हुआ कि डॉक्टर बनने का अर्थ केवल एक पेशा नहीं बल्कि किसी के जीवन में उम्मीद बनकर खड़ा होना है। जब आप किसी व्यक्ति या परिवार को आश्वासन देते है तो वही आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही भावना मुझे इस रास्ते पर ले आई।

अपने प्रोफेशनल सफर के बारे में बताइए।
एमबीबीएस के बाद मैं भी कई छात्रों की तरह आगे के रास्ते को लेकर असमंजस में था क्योंकि मैडिकल के इस क्षेत्र में दिशा अक्सर रैंक और अवसरों पर निर्भर करती है। मैंने एनेस्थेसियोलॉजी को चुना। यह एक ऐसा विभाग है जो सामने तो कम दिखाई देता है लेकिन अस्पताल के हर महत्वपूर्ण कार्य में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कार्य करते-करते समझ में आया कि इलाज के साथ-साथ अस्पताल के सिस्टम में भी सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसी सोच ने मुझे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर बढ़ाया। मेरे करियर का एक अहम मोड़ तब आया जब मुझे National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH) के साथ कार्य करने का अवसर मिला। वहाँ मैंने देखा कि सही सिस्टम और प्रक्रियाएँ ही अच्छे इलाज को लगातार संभव बनाती है। इस अनुभव ने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया।

आप ऑल्ट्रस हेल्थकेयर के निदेशक है, नेतृत्व को आप किस प्रकार परिभाषित करते है?
नेतृत्व केवल पद नहीं है। यह वह सफर है जहाँ लोग पहले आपको जिम्मेदारी के कारण मानते है, फिर विश्वास के कारण जुड़ते है और अंततः आपके काम के कारण आपका अनुसरण करते है। मेरे लिए नेतृत्व का सर्वोच्च स्तर वह है जहाँ आप खुद से ज्यादा दूसरों को आगे बढ़ाते है।

दिव्य हिमगिरी के पाठकों के लिए आपका संदेश
स्वास्थ्य को अक्सर हम तब तक नजरअंदाज करते है जब तक कोई समस्या सामने न आ जाए। अगर हम समय पर ध्यान दे, नियमित जांच कराएँ और सही जानकारी रखें तो कई परेशानियों से बचा जा सकता है। साथ ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि अस्पतालों में ऐसा माहौल बने जहां मरीज को केवल इलाज ही नहीं बल्कि भरोसा और सम्मान भी मिले।

‘अब दिल्ली दूर नहीं’

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

14 अप्रैल 2026 उत्तराखंड, खासतौर पर राजधानी देहरादून के लिए ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है। लंबे समय से जिस तेज कनेक्टिविटी का इंतजार था, वह अब हकीकत बनने वाली है। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही राजधानी वासियों का ढाई घंटे में दिल्ली पहुंचने का सपना साकार होगा। अब तक साढ़े छह घंटे या उससे अधिक समय लेने वाला यह सफर तेज रफ्तार हाईवे के जरिए बेहद आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। इस बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को देवभूमि पहुंचकर करेंगे, जिसे राज्य के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए भी खास माना जा रहा है, क्योंकि एक ओर प्रदेश को देश की राजधानी से तेज कनेक्टिविटी मिल रही है, वहीं प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा भी राजनीतिक और विकास दोनों दृष्टि से अहम है। एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पर्यटन, व्यापार और आवागमन को नई रफ्तार मिलेगी। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी जाने वाले यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत लेकर आएगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

14 अप्रैल 2026 उत्तराखंड के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत के रूप में दर्ज होने जा रहा है। वर्षों से देहरादून और दिल्ली के बीच तेज, सुगम और भरोसेमंद कनेक्टिविटी का जो सपना देखा जा रहा था, वह अब साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही राजधानी देहरादून से दिल्ली का सफर साढ़े छह घंटे से घटकर महज ढाई घंटे का रह जाएगा। यह परियोजना न सिर्फ यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएगी, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन, व्यापार और निवेश के लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। राजधानी देहरादून के लोगों के लिए यह किसी बड़े बदलाव से कम नहीं है। अब तक दिल्ली जाने के लिए लंबा और थकाऊ सफर तय करना पड़ता था, जिसमें ट्रैफिक जाम, शहरों से होकर गुजरने वाला मार्ग और समय की अनिश्चितता बड़ी समस्या रहती थी। लेकिन एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद तेज रफ्तार और सीमित प्रवेश वाले इस मार्ग से यात्रा आसान और समयबद्ध हो जाएगी। इससे रोजाना यात्रा करने वाले लोगों, कारोबारियों, पर्यटकों और छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी और दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसके बाद निर्माण कार्य को तीन चरणों में पूरा किया गया। पहला चरण दिल्ली के अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन तक, दूसरा चरण ईपीई जंक्शन से सहारनपुर बायपास तक और तीसरा चरण सहारनपुर से देहरादून तक विकसित किया गया। परियोजना के कुछ हिस्से पहले ही खोल दिए गए थे, लेकिन 14 अप्रैल को पूरा कॉरिडोर एक साथ जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर से होते हुए देहरादून तक पहुंचेगा। पुराने मार्ग की तुलना में दूरी भी कम हो जाएगी। जहां पहले यह दूरी करीब 235 किलोमीटर थी, वहीं नए एक्सप्रेसवे से यह लगभग 213 किलोमीटर रह जाएगी। उच्च गति मानकों के अनुसार 100 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार से यह सफर लगभग ढाई घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह भी है कि इससे हरिद्वार और आगे चारधाम मार्ग से जुड़ने वाला लिंक भी विकसित किया गया है। इससे ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी और पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। धार्मिक पर्यटन और पहाड़ी पर्यटन दोनों को इससे सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। सप्ताहांत पर देहरादून और मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए यह मार्ग समय और ईंधन दोनों की बचत करेगा।

12,000 करोड़ की लागत से बने इस

6-लेन एक्सप्रेसवे में आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा है

करीब 12,000 करोड़ रुपये की लागत से बने इस 6-लेन एक्सप्रेसवे में आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें 7 इंटरचेंज, 2 रेलवे ओवरब्रिज, 10 बड़े पुल और 14 वेसाइड सुविधाएं विकसित की गई हैं। इन वेसाइड सुविधाओं में यात्रियों के लिए भोजन, ईंधन, शौचालय और विश्राम की व्यवस्था होगी। लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों के लिए यह सुविधाएं सफर को और आरामदायक बनाएंगी। देहरादून से पहले आखिरी हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क के इको-सेंसिटिव जोन से होकर गुजरता है, जहां पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विशेष इंजीनियरिंग समाधान अपनाए गए हैं। डाट काली मंदिर के पास लगभग 370 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। इसके अलावा एशिया का सबसे लंबा करीब 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर भी तैयार किया गया है, जिससे जंगली जानवरों की आवाजाही प्रभावित न हो। हाथियों के लिए विशेष अंडरपास और वन्यजीवों के लिए अलग मार्ग भी बनाए गए हैं। इससे विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है। इस परियोजना के शुरू होने से दिल्ली-देहरादून मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और पारंपरिक हाईवे पर लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को इससे बड़ा लाभ होगा, क्योंकि दिल्ली और आसपास के राज्यों से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। होटल, ट्रैवल और स्थानीय व्यापार से जुड़े लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर राज्य सरकार भी व्यापक तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उद्घाटन कार्यक्रम को भव्य और सुव्यवस्थित बनाया जाए। सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, जनसभा स्थल और स्वागत कार्यक्रमों को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रशासन स्तर पर लगातार बैठकें कर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो और कार्यक्रम सुचारु रूप से संपन्न हो। राज्य सरकार इस अवसर को विकास और निवेश के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मान रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इससे राज्य की राजधानी देश की राजधानी से तेज रफ्तार कनेक्टिविटी से जुड़ेगी और पर्यटन, उद्योग तथा सेवाओं के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे।

पीएम मोदी डाटकाली मंदिर में पूजा के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत 14 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गणेशपुर पहुंचेंगे। वहां से वह सड़क मार्ग से एशिया के सबसे लंबे ग्रीन एलिवेटेड कॉरिडोर से होते हुए देहरादून सीमा पर स्थित मां डाटकाली सिद्धिपीठ मंदिर के लिए रवाना होंगे। करीब 12 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड कॉरिडोर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की सबसे खास विशेषताओं में शामिल है, जिसे वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जमीन से ऊपर बनाया गया है। प्रधानमंत्री मंदिर में लगभग 15 से 20 मिनट तक पूजा-अर्चना और दर्शन करेंगे। मां डाटकाली मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री देहरादून के घड़ी कैंट स्थित महिंद्रा ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां वह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी और आवागमन अधिक सुगम होगा। मार्गों की मरम्मत, बैरिकेडिंग, संकेतक बोर्ड और भीड़ नियंत्रण की विशेष व्यवस्था की जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में है, ताकि कार्यक्रम सुचारु रूप से संपन्न कराया जा सके।

प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज, एक्सप्रेसवे से पर्यटन और व्यापार को नई रफ्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर देहरादून में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था, सुरक्षा घेरा, यातायात नियंत्रण और स्वागत की रूपरेखा पर काम किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। सड़क मार्गों की मरम्मत, संकेतक बोर्ड, पार्किंग व्यवस्था और वीआईपी मूवमेंट को लेकर विशेष योजना बनाई जा रही है। धामी सरकार इस कार्यक्रम को राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पर्यटन विभाग, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, परिवहन और प्रशासनिक अधिकारी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी की संभावना को देखते हुए भीड़ प्रबंधन की तैयारी भी की जा रही है। एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तराखंड के पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। दिल्ली से देहरादून और आगे मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार की दूरी कम होने से वीकेंड पर्यटन बढ़ सकता है। इससे होटल उद्योग, टैक्सी संचालक, स्थानीय बाजार और छोटे व्यवसायों को फायदा होगा। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी यह मार्ग महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भी इस परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तेज कनेक्टिविटी से माल ढुलाई आसान होगी और उद्योगों को लॉजिस्टिक लाभ मिलेगा। देहरादून और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों को दिल्ली-एनसीआर से सीधा फायदा मिल सकता है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने की भी संभावना है। स्थानीय लोगों के लिए भी यह परियोजना राहत लेकर आएगी। अब तक लंबी यात्रा और जाम की समस्या से जूझने वाले यात्रियों को तेज और सुरक्षित मार्ग मिलेगा। सड़क सुरक्षा मानकों के अनुसार विकसित एक्सप्रेसवे दुर्घटनाओं को कम करने में भी मदद करेगा। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किए गए उपाय इस परियोजना को खास बनाते हैं। एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर, अंडरपास और सुरंग जैसे समाधान विकास और प्रकृति के संतुलन का उदाहरण माने जा रहे हैं। इससे राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में वन्यजीवों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। 14 अप्रैल को एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही देहरादून और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी का नया अध्याय शुरू होगा। यह परियोजना उत्तराखंड के विकास, पर्यटन और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि यह एक्सप्रेसवे राज्य को नई रफ्तार देगा और देहरादून को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से और मजबूती से जोड़ेगा।

चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का सख्त एक्शन प्लान

19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालु-हितैषी बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त एक्शन प्लान तैयार कर दिया है। सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनशीलता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री ने ग्रीन एवं क्लीन यात्रा अभियान को और व्यापक बनाने, प्लास्टिक पर पूरी तरह लगाम लगाने और यात्रा मार्गों पर कलेक्शन बॉक्स स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही भीड़ नियंत्रण के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग और स्लॉट सिस्टम लागू करने, हेली सेवाओं में नियमित मेंटेनेंस व फिटनेस जांच अनिवार्य करने तथा ओवररेटिंग रोकने के लिए हर दुकान पर रेट लिस्ट प्रदर्शित करने को कहा गया। स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय और शेल्टर की व्यवस्थाओं को मजबूत करने, ट्रैफिक जाम रोकने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार रखने और सीसीटीवी व एआई आधारित निगरानी लागू करने के निर्देश भी दिए गए। अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर और 24x7 कंट्रोल रूम के जरिए त्वरित रिस्पांस सुनिश्चित किया जाएगा। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

चारधाम यात्रा-2026 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में व्यापक निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस वर्ष यात्रा 19 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही है, ऐसे में सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं। अक्षय तृतीया के अवसर पर 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ यात्रा का शुभारंभ होगा, जबकि 22 अप्रैल को केदारनाथ और 24 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा यात्रा को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाए। सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यात्रा संचालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनशीलता को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ग्रीन एवं क्लीन चारधाम यात्रा अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए यात्रा मार्गों को प्लास्टिक मुक्त बनाने, जगह-जगह कलेक्शन बॉक्स लगाने और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। हेली सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सभी हेलीकॉप्टरों की नियमित मेंटेनेंस और फिटनेस जांच अनिवार्य की जाए। ऑपरेशनल ओवरलोडिंग से बचने के लिए सेवाओं को समय-समय पर पर्याप्त विश्राम दिया जाए तथा निर्धारित मानकों का पूरी सख्ती से पालन किया जाए। मौसम आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने प्रमुख स्थलों पर सेल्फी प्वाइंट, थीम आधारित इंस्टॉलेशन और यात्रा मार्गों पर सौंदर्यीकरण कार्य तेज करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि यात्रा मार्गों पर गैस, पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

यात्रा मार्गों पर अधिकारियों को दैनिक मॉनिटरिंग करने के दिए निर्देश

सीएम धामी ने जिला पूर्ति अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर अलग-अलग नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा दैनिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए यात्रा मार्गों पर पर्याप्त मेडिकल यूनिट्स, अस्थायी अस्पताल और एंबुलेंस तैनात करने के निर्देश दिए गए। पशुओं के उपचार के लिए पशु चिकित्सालयों की संख्या बढ़ाने तथा स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने

पर भी जोर दिया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने यात्रा मार्गों पर शौचालय, विश्राम स्थल और शेल्टर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दर्शन के लिए लंबा इंतजार न हो, इसके लिए स्लॉट मैनेजमेंट और भीड़ नियंत्रण प्रणाली प्रभावी रूप से लागू की जाए तथा रियल-टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग किया जाए। ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली को मजबूत करने, भीड़भाड़ वाले केंद्रों पर अतिरिक्त बूथ बढ़ाने और प्रक्रिया को सरल बनाने को कहा गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने और आवश्यकता अनुसार एआई आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने के निर्देश भी दिए गए। कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने मुख्य मार्गों, चौराहों और बाजारों में पुलिस और होमगार्ड्स की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए सख्त ट्रैफिक प्लान लागू करने और स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार रखने के निर्देश दिए गए। आपदा प्रबंधन के तहत संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर संसाधनों की तैनाती करने तथा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को अलर्ट मोड में रखने को कहा गया। 24x7 कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओवररेटिंग पर सख्ती करते हुए सभी दुकानों पर रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। पिछले वर्ष भंडारों को लेकर हुए विवादों का उल्लेख करते हुए प्रशासन को स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच समन्वय स्थापित कर स्थायी समाधान निकालने को कहा गया। परिवहन व्यवस्था को लेकर सभी वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड समय पर उपलब्ध कराने तथा सड़क मार्गों की स्थिति दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए गए। यात्रा मार्गों पर गड्ढों को तत्काल भरने और सड़क सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज (वर्चुअल माध्यम से), मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संबंधित जिलों के जिलाधिकारी तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यात्रा अवधि के दौरान नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से तैयारियों की निगरानी की जाए और आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कदम तुरंत लागू किए जाएं, ताकि चारधाम यात्रा-2026 श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुगम और बेहतर अनुभव वाली बन सके।

चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड में मेगा मॉक ड्रिल आयोजित

उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए यात्रा मार्ग से जुड़े जिलों में व्यापक स्तर पर "मोंट्रियल एक्सरसाइज" के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास में आपदा प्रबंधन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरफ और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। अभ्यास के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, सड़क हादसों, हेलीकॉप्टर दुर्घटना, आग, बाढ़, भूस्खलन और भीड़ प्रबंधन जैसी कई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां तैयार कर राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखा गया। साथ ही हजारों यात्रियों के फंसने, संचार व्यवस्था ठप होने और सीमित संसाधनों के बीच त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पर विशेष फोकस किया गया, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय को कम किया जा सके। चमोली जिले में बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर सबसे चुनौतीपूर्ण हालात तैयार किए गए। पागल नाला और गुंडाला क्षेत्र में भारी भूस्खलन और शूटिंग स्टोन की घटनाओं में हजारों यात्रियों के फंसने की स्थिति बनाई गई। बद्रीनाथ मंदिर क्षेत्र में भूकंप के बाद भगदड़, पुल से लोगों के नदी में गिरने और डूबने जैसी स्थितियों पर रेस्क्यू अभ्यास किया गया। इसके अलावा गौचर के पास बस दुर्घटना, जोशीमठ के होटल में आग और खराब मौसम के बीच जोशीमठ-बद्रीनाथ मार्ग पर 3000 से अधिक यात्रियों के फंसने की स्थिति में राहत कार्यों का अभ्यास हुआ। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री और गंगोत्री मार्ग पर बादल फटना, फ्लैश फ्लड और ग्लेशियर झील फटने जैसी स्थितियों का अभ्यास किया गया। यमुनोत्री ट्रैक पर भूस्खलन में खच्चरों के गिरने और यात्रियों के घायल होने पर मेडिकल रेस्क्यू किया गया। पालीगढ़ क्षेत्र में बादल फटना और स्यानाचट्टी में नदी रुकने से झील बनने जैसी स्थिति में बाढ़ के खतरे से निपटने की रणनीति का परीक्षण किया गया। गंगोत्री क्षेत्र में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बाद शहर में तबाही और यात्रियों के फंसने की स्थिति में बड़े पैमाने पर निकासी अभियान चलाया गया। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बादल फटना, फ्लैश फ्लड और ट्रेकिंग रूट टूटने की स्थिति बनाई गई। इसमें 400 से 500 यात्रियों के फंसे होने पर उनका रेस्क्यू करने का अभ्यास किया गया। फाटा और गौरीकुंड क्षेत्र में भूस्खलन, हेलीकॉप्टर दुर्घटना, बस हादसे और खराब मौसम के बीच 3000 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की रणनीति का परीक्षण किया गया। देहरादून जिले में मसूरी रोड पर सड़क हादसे और ट्रैफिक जाम में हजारों वाहनों के फंसने की स्थिति बनाई गई। डाकपत्थर बैराज पर अचानक जलस्तर बढ़ने से यात्रियों के बहने और फंसने की स्थिति में रेस्क्यू अभ्यास किया गया। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में आग, भगदड़ और रेड अलर्ट के दौरान 5000 से अधिक यात्रियों के जमाव जैसी परिस्थितियों में प्रशासन की तैयारियों को परखा गया। हरिद्वार में हर की पौड़ी और रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन का अभ्यास किया गया। गंगा घाट पर भगदड़ के दौरान यात्रियों के बहने की स्थिति बनाई गई, जबकि रेलवे स्टेशन पर अचानक भीड़ बढ़ने, सुरंग में ट्रेन फंसने और बम की अफवाह फैलने जैसे हालात में सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया का परीक्षण किया गया। पौड़ी जिले में बद्रीनाथ-केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन से 300 से अधिक वाहनों के फंसने की स्थिति बनाई गई। श्रीनगर में होटल में आग, ट्रैफिक जाम और भूकंप के बाद राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास हुआ। देवप्रयाग क्षेत्र में बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ जैसे हालात में यात्रियों को सुरक्षित निकालने की रणनीति पर काम किया गया। टिहरी जिले में चंबा-उत्तरकाशी मार्ग पर भूस्खलन और शूटिंग स्टोन से सड़क बंद होने पर 300 से अधिक वाहनों के फंसने का अभ्यास किया गया। कीर्तिनगर और मलेथा क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम, तोता घाटी में सड़क हादसा और टिहरी बांध से पानी छोड़े जाने पर निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति में राहत अभियान चलाया गया। इस मेगा मॉक ड्रिल के माध्यम से चारधाम यात्रा के दौरान संभावित खतरों से निपटने की तैयारियों का व्यापक परीक्षण किया गया। अलग-अलग जिलों में जमीनी स्तर पर आपदा की संभावनाएं बनाकर विभागों के आपसी समन्वय, संसाधनों की उपलब्धता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को परखा गया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति में समय पर राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करना और संभावित नुकसान को न्यूनतम रखना है।

टोल प्लाजा पर नगद भुगतान खत्म

नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है। 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नगद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है और अब टोल शुल्क केवल फास्टैग या यूपीआई के माध्यम से ही लिया जा रहा है। नए नियम के तहत जिन वाहनों में फास्टैग नहीं है या वह सक्रिय नहीं है, उन्हें यूपीआई से भुगतान करने की अनुमति तो होगी, लेकिन इसके लिए तय टोल से 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। वहीं, जिन वाहनों का फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है या बैलेंस कम है और वे फास्टैग लेन में प्रवेश करते हैं, उनसे दोगुना टोल वसूला जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर वाहन मालिकों को एसएमएस और ईमेल के जरिए ई-नोटिस भेजा जाएगा, जिसका जवाब देने या जुर्माना भरने के लिए तीन दिन का समय मिलेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य टोल प्लाजा पर भीड़ कम करना और वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत हो सके। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट

नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए टोल भुगतान व्यवस्था में बड़ा और निर्णायक बदलाव लागू कर दिया गया है। 10 अप्रैल से देश के कई टोल प्लाजा पर नगद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है और अब टोल शुल्क केवल फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही लिया जा रहा है। इस नए नियम के लागू होते ही टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान व्यवस्था अनिवार्य हो गई है, जिससे बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करना, वाहनों की आवाजाही को तेज करना और ईंधन की बचत सुनिश्चित करना है। नए नियमों के अनुसार, जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है या फास्टैग सक्रिय नहीं है, वे चालक यूपीआई के माध्यम से टोल का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि, इस स्थिति में उन्हें तय टोल शुल्क से 25 प्रतिशत अधिक राशि देनी होगी। यानी यदि किसी वाहन का टोल 100 रुपये है, तो यूपीआई के जरिए भुगतान करने पर उसे 125 रुपये चुकाने होंगे। यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि वाहन चालक फास्टैग का उपयोग करें और टोल भुगतान पूरी तरह डिजिटल माध्यम से हो सके। इसके अलावा, जिन वाहनों का फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है या उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। ऐसे वाहन यदि फास्टैग लेन में प्रवेश करते हैं, तो उनसे दोगुना टोल वसूला जाएगा। यह नियम पहले भी लागू था, लेकिन अब इसकी सख्ती बढ़ा दी गई है और निगरानी को अधिक डिजिटल बना दिया गया है। टोल प्लाजा पर लगे सेंसर और कैमरे वाहनों की पहचान कर तुरंत डेटा दर्ज करेंगे, जिससे नियमों के उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। नए सिस्टम के तहत नियम तोड़ने वाले वाहन मालिकों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से ई-नोटिस भेजा जाएगा। इस नोटिस में जुर्माना राशि, समयसीमा और भुगतान के विकल्प की जानकारी दी जाएगी। वाहन मालिकों को तीन दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें वे जुर्माना भर सकते हैं या विवाद दर्ज करा सकते हैं। तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर अतिरिक्त दंड भी लगाया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि नगद भुगतान की वजह से टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती थीं। भुगतान में समय लगता था और कई बार छुट्टे पैसों को लेकर विवाद भी होते थे। इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती थी और यात्रियों का समय भी बर्बाद होता था। अब डिजिटल भुगतान व्यवस्था लागू होने से वाहन बिना रुके आगे बढ़ सकेंगे और टोल प्लाजा पर रुकने का समय कम हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुताबिक यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। जिन टोल प्लाजा पर अभी पूरी तरह व्यवस्था लागू नहीं हुई है, वहां भी जल्द ही नगद भुगतान समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए टोल प्लाजा पर यूपीआई क्यूआर कोड, डिजिटल डिस्प्ले और ऑटोमेटेड भुगतान प्रणाली लगाई जा रही है, जिससे वाहन चालक आसानी से भुगतान कर सकें। इस बदलाव के बाद टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की भूमिका भी बदली जा रही है। अब उनका फोकस नगद वसूली के बजाय डिजिटल भुगतान को सुचारु रूप से संचालित करने पर रहेगा। साथ ही वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए टोल प्लाजा पर घोषणाएं और सूचना बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी चालक नियमों से अनजान न रहे।

डिजिटल टोल व्यवस्था से भीड़ कम करने और समय बचाने पर जोर

नए नियम लागू करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य टोल प्लाजा पर भीड़ को कम करना और यातायात को सुचारु बनाना है। मंत्रालय का मानना है कि नगद भुगतान खत्म होने से वाहनों को लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टोल पार करने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। इससे यात्रियों का कीमती समय बचेगा और ईंधन की खपत भी घटेगी, जो पर्यावरण के लिहाज से भी फायदेमंद माना जा रहा है। फास्टैग आधारित टोल प्रणाली पहले से ही लागू है, लेकिन नगद भुगतान की सुविधा होने से कई वाहन चालक फास्टैग का उपयोग नहीं करते थे। अब नगद भुगतान पूरी तरह बंद होने से सभी वाहन चालकों को डिजिटल माध्यम अपनाना होगा। इससे टोल वसूली पारदर्शी बनेगी और राजस्व संग्रह में भी सुधार होने की उम्मीद है। टोल प्लाजा पर अब यूपीआई भुगतान के लिए अलग व्यवस्था की गई है। जिन वाहनों में फास्टैग नहीं है, उन्हें निर्धारित लेन में रोककर यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान कराया जाएगा। भुगतान की पुष्टि होते ही वाहन को आगे बढ़ने की अनुमति मिल जाएगी। हालांकि इस प्रक्रिया में अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, ताकि वाहन चालक फास्टैग लगवाने को प्राथमिकता दें। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वाहन चालकों को फास्टैग सक्रिय रखने और उसमें पर्याप्त बैलेंस बनाए रखने की सलाह दी गई है। यदि फास्टैग ब्लैकलिस्टेड पाया

जाता है या उसमें बैलेंस कम है, तो वाहन को दोगुना टोल देना पड़ेगा। साथ ही बार-बार नियम तोड़ने पर वाहन के खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई भी की जा सकती है। नए नियम लागू होने के बाद कई टोल प्लाजा पर ट्रैफिक की स्थिति में सुधार देखने को मिला है। डिजिटल भुगतान होने से वाहनों की आवाजाही तेज हुई है और कतारों की लंबाई कम हुई है। हालांकि शुरुआती दिनों में कुछ वाहन चालकों को परेशानी भी हुई, खासकर उन लोगों को जिनके पास फास्टैग नहीं था या यूपीआई भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अधिकारियों का कहना है कि यह अस्थायी स्थिति है और जल्द ही सभी वाहन चालक नई व्यवस्था के अनुसार खुद को ढाल लेंगे। मंत्रालय का मानना है कि आने वाले समय में टोल भुगतान पूरी तरह स्वचालित हो जाएगा, जहां वाहन को बिना रोके ही टोल कट जाएगा। इसके लिए जीपीएस आधारित टोल प्रणाली पर भी काम चल रहा है। फिलहाल नगद भुगतान बंद करने का फैसला उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए नियम के लागू होने के बाद वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपने फास्टैग की स्थिति जांच लें और उसमें पर्याप्त बैलेंस रखें। इससे अतिरिक्त शुल्क और दोगुना टोल देने से बचा जा सकेगा। वहीं, जिन वाहन चालकों के पास फास्टैग नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द फास्टैग लगवाने की सलाह दी जा रही है, ताकि टोल प्लाजा पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में मोबाइल पर प्रतिबंध

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। बढ़ते स्क्रीन टाइम, पढ़ाई में गिरावट और अनुशासन संबंधी शिकायतों के बीच जारी नए निर्देशों में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए मोबाइल उपयोग सीमित कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक छात्र स्कूल समय में मोबाइल फोन साथ नहीं लाएंगे, जबकि विशेष परिस्थिति में लाने पर उसे स्कूल प्रशासन के पास जमा कराना होगा। कक्षा के दौरान मोबाइल का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। विभाग का कहना है कि मोबाइल की वजह से बच्चों की एकाग्रता प्रभावित हो रही है, साथ ही उनकी दिनचर्या और व्यवहार पर भी असर पड़ रहा है। शिक्षकों को भी केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए ही मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। निजी कॉल, सोशल मीडिया या अन्य गैर-जरूरी उपयोग पर रोक रहेगी। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही छात्रों में डिजिटल अनुशासन विकसित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया है। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों के स्क्रीन टाइम पर नजर रखें। विभाग का मानना है कि इस पहल से स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा और छात्रों का ध्यान पढ़ाई व रचनात्मक गतिविधियों की ओर बढ़ेगा। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के मोबाइल इस्तेमाल को लेकर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। बच्चों में तेजी से बढ़ रही मोबाइल की लत, पढ़ाई में गिरावट और अनुशासन से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार स्कूल समय में मोबाइल का उपयोग सीमित रहेगा और कक्षा के दौरान इसका इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। विभाग का मानना है कि मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से छात्रों की एकाग्रता प्रभावित हो रही है और उनका ध्यान पढ़ाई से भटक रहा है। नए निर्देशों के मुताबिक छात्र स्कूल समय में मोबाइल फोन साथ नहीं लाएंगे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में मोबाइल लाना जरूरी हो, तो उसे स्कूल प्रशासन के पास जमा कराना होगा और छुट्टी के समय वापस दिया जाएगा। इसके लिए स्कूलों को मोबाइल जमा करने की अलग व्यवस्था बनाने और जिम्मेदार अधिकारी तय करने को कहा गया है। कक्षा के दौरान मोबाइल का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। स्कूल परिसर में भी अनावश्यक मोबाइल इस्तेमाल पर रोक रहेगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शिक्षकों को केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन सामग्री या डिजिटल लर्निंग के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकेगा, लेकिन निजी कॉल, सोशल मीडिया या अन्य गैर-जरूरी उपयोग पर रोक रहेगी। विभाग ने कहा है कि शिक्षक छात्रों के सामने अनुशासन का उदाहरण प्रस्तुत करें ताकि स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर बने। विभाग के अनुसार कई स्कूलों से शिकायत मिल रही थी कि छात्र कक्षा के दौरान मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल के कारण नींद की कमी और सुबह स्कूल में थकान की समस्या भी सामने आ रही थी। इससे छात्रों की एकाग्रता कम हो रही थी और परीक्षा परिणामों पर भी असर पड़ रहा था। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से बच्चों में आंखों से जुड़ी समस्याएं, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और व्यवहार में बदलाव जैसी शिकायतें बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया के कारण अनुशासनहीनता और पढ़ाई से दूरी के मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने और छात्रों को पढ़ाई की ओर प्रेरित करने के लिए मोबाइल उपयोग पर नियंत्रण जरूरी माना गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे छात्रों का ध्यान कक्षा में अधिक रहेगा और वे खेलकूद तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाएंगे।

डिजिटल अनुशासन बढ़ाने के साथ जागरूकता अभियान भी शुरू:

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय मोबाइल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं, बल्कि उसके नियंत्रित और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। जरूरत पड़ने पर स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन सामग्री या डिजिटल लर्निंग के लिए मोबाइल या अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जा सकेगा। हालांकि इसका इस्तेमाल केवल पढ़ाई तक सीमित रहेगा और शिक्षक की निगरानी में ही होगा। इसके साथ ही सभी स्कूलों को छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रार्थना सभा, विशेष कक्षाओं और कार्यशालाओं के माध्यम से मोबाइल के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाएगी। छात्रों को बताया जाएगा कि सीमित स्क्रीन टाइम उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। शिक्षकों को भी कक्षा के दौरान अनावश्यक मोबाइल उपयोग से बचने और छात्रों के सामने सकारात्मक उदाहरण पेश करने को कहा गया है। अभिभावकों की भूमिका को भी इस पहल में महत्वपूर्ण बताया गया है। विभाग ने माता-पिता से अपील की है कि वे बच्चों को कम उम्र में स्मार्टफोन देने से बचें और घर पर उनके स्क्रीन टाइम पर निगरानी रखें। पढ़ाई के समय मोबाइल से दूरी बनाने की आदत विकसित करने पर जोर दिया गया है। स्कूलों को अभिभावक-शिक्षक बैठकों में इस विषय पर चर्चा कर संयुक्त रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि इस फैसले से स्कूलों में अनुशासन मजबूत होगा और पढ़ाई का माहौल बेहतर बनेगा। मोबाइल के नियंत्रित उपयोग से छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी और वे खेलकूद, पुस्तक पठन तथा रचनात्मक गतिविधियों में अधिक भागीदारी करेंगे। माना जा रहा है कि स्कूल और अभिभावकों के संयुक्त प्रयास से बच्चों में डिजिटल अनुशासन विकसित होगा और उनका शैक्षणिक प्रदर्शन भी बेहतर होगा।

दून पुस्तक महोत्सव में दिग्गजों के संवाद से सजा मंच

देहरादून में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से आयोजित दून पुस्तक महोत्सव 2026 का आगाज 4 अप्रैल से परेड ग्राउंड में हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। नौ दिवसीय इस महोत्सव का समापन 12 अप्रैल को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और संवाद सत्रों के साथ होगा। पूरे आयोजन के दौरान साहित्य, सिनेमा, इतिहास, अध्यात्म, नेतृत्व, खोजी पत्रकारिता और आधुनिक तकनीक जैसे विविध विषयों पर गहन चर्चाएं हुईं। जुपिंदर सिंह, अद्वैता काला, आचार्य प्रशांत, इम्तियाज अली, शुभांशु शुक्ला और लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ सहित कई दिग्गज हस्तियों ने मंच साझा कर युवाओं और पाठकों से संवाद किया। पैनल चर्चाओं, पुस्तक विमोचन, इंटरैक्टिव सत्र और क्षेत्रीय साहित्य पर विशेष कार्यक्रम महोत्सव के प्रमुख आकर्षण रहे। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, पाठकों और साहित्य प्रेमियों ने भाग लेकर लेखकों से सीधे बातचीत की। समापन दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को जीवंत बनाया, जिसमें मेहर सिंह ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया और महोत्सव का समापन यादगार बना। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

देहरादून में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित दून पुस्तक महोत्सव 2026 इन दिनों साहित्य प्रेमियों, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। 4 अप्रैल से परेड ग्राउंड में शुरू हुआ यह नौ दिवसीय आयोजन 12 अप्रैल तक चलेगा और 11 अप्रैल तक महोत्सव में लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तकें समाज को दिशा देने का सबसे सशक्त माध्यम हैं और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में भी किताबों का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि नई पीढ़ी को विचारशील बनाने में पुस्तकों की भूमिका और अधिक बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दून पुस्तक महोत्सव जैसे आयोजन ज्ञान, संवाद और विचारों के आदान-प्रदान का मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे किताबों से जुड़ें, पढ़ने की आदत विकसित करें और अपने व्यक्तित्व के विकास में साहित्य को शामिल करें। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा बेहद समृद्ध रही है और ऐसे आयोजन इस विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने आयोजन में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और प्रकाशकों, लेखकों तथा विद्यार्थियों से बातचीत की। महोत्सव में देशभर के प्रकाशकों के सैकड़ों पुस्तक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां साहित्य, इतिहास, विज्ञान, तकनीक, अध्यात्म, बच्चों की किताबें, प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें और क्षेत्रीय साहित्य की बड़ी श्रृंखला उपलब्ध है। बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अभिभावक यहां पहुंचकर किताबों की खरीदारी कर रहे हैं। कई प्रकाशकों ने विशेष छूट भी दी है, जिससे पाठकों की रुचि और बढ़ी है।

महोत्सव के दौरान साहित्य, सिनेमा, खोजी पत्रकारिता, पटकथा लेखन, अध्यात्म, नेतृत्व,

क्षेत्रीय साहित्य और रक्षा जैसे विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। विभिन्न मंचों पर लेखकों और वक्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए और दर्शकों से संवाद किया। जुपिंदर सिंह ने खोजी पत्रकारिता पर अपने अनुभव साझा करते हुए मीडिया की जिम्मेदारी पर विस्तार से चर्चा की।

अद्वैता काला ने लेखन प्रक्रिया, कहानी कहने की कला और महिलाओं की भूमिका पर बात की। आचार्य प्रशांत ने अध्यात्म और आधुनिक जीवन के बीच संतुलन पर विचार रखे। फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली ने पटकथा लेखन और सिनेमा की रचनात्मक प्रक्रिया पर युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि कहानी वहीं से जन्म लेती है जहां संवेदनाएं और अनुभव मिलते हैं। शुभांशु शुक्ला ने नेतृत्व और युवा सोच पर अपने विचार रखे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रेरक अनुभवों को साझा किया। इन सत्रों में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और सवाल-जवाब के माध्यम से वक्ताओं से संवाद किया। महोत्सव में बच्चों के लिए विशेष गतिविधियां भी आयोजित की गईं। कहानी सुनाने के सत्र, चित्रकला प्रतियोगिता, क्विज कार्यक्रम और इंटरैक्टिव कार्यशालाएं बच्चों के आकर्षण का केंद्र बनीं। वहीं क्षेत्रीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के लेखकों और लोक साहित्य पर आधारित सत्र आयोजित किए गए। पुस्तक विमोचन कार्यक्रमों में कई नई पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी महोत्सव को जीवंत बनाए रखा। लोक नृत्य, संगीत प्रस्तुतियां और युवा कलाकारों के कार्यक्रम दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। शाम के समय बड़ी संख्या में लोग सांस्कृतिक मंच के सामने जुट रहे हैं। आयोजन स्थल पर सेल्फी प्वाइंट, पठन कोना और इंटरैक्टिव जोन भी बनाए गए हैं, जहां लोग समय बिता रहे हैं। महोत्सव में लगातार भीड़ बढ़ती देखी जा रही है। सप्ताहांत से पहले ही विद्यार्थियों और परिवारों की बड़ी संख्या पहुंच रही है। आयोजकों के अनुसार समापन दिवस तक और अधिक लोगों के आने की संभावना है।

दिग्गजों के सत्र, पुस्तक विमोचन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बने मुख्य आकर्षण

महोत्सव के मध्य दिनों में कई महत्वपूर्ण पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं, जिनमें साहित्य और समाज के बदलते स्वरूप पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि पढ़ने की आदत समाज को अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाती है। तकनीक और सोशल मीडिया के दौर में भी किताबों की प्रासंगिकता पर जोर दिया गया। युवा पाठकों ने भी अपने अनुभव साझा किए और लेखकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। आयोजन में क्षेत्रीय साहित्य को विशेष स्थान दिया गया है। उत्तराखंड की लोक परंपरा, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया। स्थानीय लेखकों ने अपने अनुभव साझा किए और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का संदेश दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए विशेष मार्गदर्शन सत्र भी आयोजित किए गए। महोत्सव में डिजिटल प्रकाशन और ई-बुक्स पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लेखन और पढ़ने के नए अवसर खोले हैं, लेकिन मुद्रित पुस्तकों का महत्व अभी भी कायम है। कई तकनीकी सत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंटेंट निर्माण पर भी चर्चा की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोक कलाकारों ने पारंपरिक प्रस्तुतियां दीं। युवाओं ने संगीत और नृत्य के कार्यक्रम पेश किए। शाम के समय साहित्यिक पाठ और कवि सम्मेलन ने माहौल को और जीवंत बनाया। आयोजन स्थल पर परिवारों के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे लोग आराम से कार्यक्रमों में भाग ले सकें। आयोजकों के अनुसार महोत्सव का उद्देश्य पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना और पाठकों को लेखकों से जोड़ना है। इस वर्ष बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेजों के छात्रों ने समूहों में भाग लिया। शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। समापन दिवस से पहले 11 अप्रैल तक आयोजित कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक देखी गई। इंटरैक्टिव सत्रों में छात्रों ने लेखन, पत्रकारिता और सिनेमा से जुड़े सवाल पूछे। कई प्रतिभागियों ने इसे प्रेरणादायक अनुभव बताया। दून पुस्तक महोत्सव के अंतिम दिनों में और पुस्तक विमोचन, लेखक संवाद और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तावित हैं। समापन दिवस पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कलाकारों की प्रस्तुति के साथ महोत्सव का समापन होगा। मेहर सिंह समापन समारोह में प्रस्तुति देंगे, जो कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण माना जा रहा है। दून पुस्तक महोत्सव 2026 ने देहरादून को एक बार फिर साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया है। लगातार बढ़ती भीड़, दिग्गज वक्ताओं के संवाद और विविध कार्यक्रमों ने इसे यादगार आयोजन बना दिया है। आयोजकों को उम्मीद है कि अंतिम दिन तक यह महोत्सव पाठकों और युवाओं के लिए ज्ञान, प्रेरणा और संवाद का बड़ा मंच साबित होगा।

बैशाखी पर हुई थी खालसा पंथ की स्थापना

डॉ श्रीगोपाल नारसन
एडवोकेट

बैसाखी सिखों का पवित्र त्योहार है। सन् 1699 में इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस पंथ की स्थापना का लक्ष्य धर्म और नेकी के रास्ते पर चलना और उसका पालन करना है। किसान अपनी फसल काटने की खुशी में यह त्योहार मनाते हैं, पंजाब में इस दिन गिद्दा-भांगड़ा किया जाता है। इस दिन को सिक्खों के नए साल के रूप में भी मनाये जाने की भी परंपरा है। बैसाखी, जिसे मेष संक्रांति भी कहा जाता है, भारतीय भारतीय समाज की संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।

यह दिन न केवल कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सिखों के लिए एक ऐतिहासिक और धार्मिक दिवस है। इस दिन का उत्सव कृषि, समाज, और धर्म के संगम का प्रतीक है, जहां लोग खुशी और समृद्धि की कामना करते हैं और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। बैसाखी का पर्व भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस साल यह पर्व 13 अप्रैल, को मनाया जा रहा है। इस दिन की महत्ता कृषि क्षेत्र में काम करने वाले किसानों के लिए बहुत अधिक है, क्योंकि यह नई फसल की बुवाई और कटाई का समय होता है। यह दिन खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। बैसाखी पर सिख धर्मावलंबी गुरुद्वारों में विशेष पूजा और अरदास करते हैं।

इस दिन विशेष रूप से गुरुद्वारों में भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाता है और नगर कीर्तन की परंपरा निभाई जाती है। लोग इस दिन को अपने पवित्र कर्तव्यों को याद करने, गुरु के बताए मार्ग पर चलने और धर्म के प्रति अपनी आस्था को और गहरा करने का अवसर मानते हैं। बैसाखी का पर्व सिख धर्म के लिए एक समय होता है जब वे अपने गुरु की शिक्षा और खालसा पंथ के महत्व को मानते हुए एकजुट होते हैं और समाज में शांति, भाईचारे और समानता का प्रचार करते हैं। बैसाखी रबी की फसल उत्सव है, जिसका कृषि महत्व के साथ-साथ धार्मिक महत्व भी है।

यह त्योहार भगवान इंद्र की पूजा से जुड़ा है, जिन्हें बारिश और उर्वरता का देवता माना जाता है। इस दिन, किसान अपनी भरपूर फसल के लिए भगवान इंद्र को धन्यवाद देते हैं और अपनी भविष्य की फसलों के लिए अच्छी बारिश की प्रार्थना करते हैं। बैशाखी के दिन की शुरुआत गंगा नदी या अन्य पवित्र नदियों में पवित्र डुबकी लगाने से होती है, इसके बाद गुरुद्वारों में जाकर प्रार्थना की जाती,मत्था टेका जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और अपने प्रियजनों के साथ मिठाइयाँ और उपहारों का आदान-प्रदान करते हैं।बैसाखी के मुख्य अनुष्ठानों में से श्भांगड़ाश और श्गिद्दाश का प्रदर्शन भी है, जो पारंपरिक पंजाबी नृत्य हैं।

जिसके माध्यम से फसल के मौसम की खुशी और उत्सव को दर्शाते हैं। इस अवसर पर लोग विशेष व्यंजन भी तैयार करते हैं जैसे 'लंगर', गुरुद्वारों में परोसा जाने वाला सामुदायिक भोजन, और 'खीर', ताजा गुड़ से बना मीठा चावल का हलवा बनाया जाता है। बैसाखी सिर्फ एक त्योहार नहीं है; बल्कि यह लोगों के जीवन में खुशियों का प्रतीक है। यह सिख धर्म मे नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और एक नए कृषि मौसम की शुरुआत का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह त्योहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सन् 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ के गठन की याद दिलाता है। इसलिए, बैसाखी को खुशी, आशा और नई शुरुआत के दिन के रूप में मनाया जाता है। बैसाखी पर्व, जो व्यक्तियों को अपनी यात्रा पर विचार करने, नकारात्मकता को त्यागने और सकारात्मकता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। बैसाखी भरपूर फसल के लिए कृतज्ञता की भावना, समुदाय की भावना को बढ़ावा देने और लोगों के बीच खुशियों को साझा करने की भावना का प्रतीक है। यह श्रम के फल का आनंद लेने, ढोल की थाप पर नृत्य करने और शानदार पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेने का समय है।एक बार 10वें सिख गुरु ने पूछा कि हजारों की भीड़ में कौन धर्म के लिए मरने को तैयार है। आखिरकार पाँच लोग स्वेच्छा से आगे आए और गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हें बपतिस्मा दिया, जिसके बाद वे खालसा समूह के पहले पाँच सदस्य यानि पंच प्यारे बन गए।

(लेखक आध्यात्मिक चिंतक एवं वरिष्ठ पत्रकार है)

देहरादून में इनडोर केसर की फार्मिंग कर रहे हैं पूर्व नौसेना अधिकारी

कैप्टन उपेंद्र अग्रवाल (रिटायर्ड)
भारतीय नौसेना

दिव्य हिमगिरि रूबरू के इस अंक में हमारे साथ हैं पूर्व नौसेना अधिकारी उपेन्द्र अग्रवाल जो देहरादून में इनडोर केसर (लैब आधारित) की फार्मिंग कर रहे हैं। इंडियन नेवी से जैविक किसानी तक के उनके इस सफर के बारे मे उनसे बात कर रहे हैं लोकेश राज अस्थाना

अपनी पारिवारिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं?

मैं एक आध्यात्मिक और धार्मिक परिवार से हूँ। मेरे माता-पिता आर्य समाज के अनुयायी हैं जहाँ नैतिक व सामाजिक मूल्य सर्वोपरि हैं। मेरे परिवार की जड़ें हरियाणा में हैं लेकिन मेरे दादाजी ने व्यवसाय के लिए कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया। बड़े होते हुए मैंने देशभक्ति, निष्ठा और समुदाय में रहने की महत्वता सीखी। मेरे माता पिता ने सुनिश्चित किया कि हम अपनी सामाजिक, धार्मिक व घरेलू जिम्मेदारियाँ को समझे और साझा करें। हम आर्य समाज की सभाओं में जाते थे जहाँ हमने सम्मान, दया और समुदाय में रहने के मूल्यों को सीखा। हम विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते है जैसे भोजन परोसना, सफाई करना, और बुजुर्गों की देखभाल करना। इसने हमें टीमवर्क, जिम्मेदारी और सामाजिक कौशल सिखाया। मैंने स्वच्छता और संगठन की आदत विकसित की जो मुझे नौसेना में काम आई। मैंने मार्शल आर्ट, योग और नौकायन सीखा है और वर्तमान में मैं कृषि और जैविक खेती के बारे में सीख रहा हूँ। मैं निरंतर सीखने और अपने कौशल को बढ़ाने में विश्वास करता हूँ। मैंने भारतीय नौसेना में 27 वर्ष सेवा की जहाँ मैं विभिन्न बंदरगाहों पर तैनात रहा और कई कार्य किये। मैंने 2 युद्धपोत जहाजों की कमान भी संभाली। ये 27 साल मेरे लिए बहुत ही संतोषजनक रहे। मेरी पत्नी एक गृहिणी हैं और हमारे दो बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा आईआईटी धनबाद में है और मेरा छोटा बेटा ११वीं कक्षा में है। मैं अपने परिवार के मूल्यों और समर्थन के लिए उनका आभारी हूँ जिसने मेरे सफलता में योगदान दिया है। मैं एक ऐसे परिवार का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करता हूँ जो परंपरा, समुदाय और व्यक्तिगत विकास को महत्व देता है।

वर्तमान में आप कॉरपोरेट में कार्यरत है और प्रगतिशील किसान के रूप में केसर की खेती भी कर रहे हैं। यह जय जवान जय किसान का एक आदर्श उदाहरण है। यह विचार मन में कैसे आया?

मैं कुवैत में एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ जो युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से भूमि विस्फोटक पदार्थो को साफ करती है। मैं हमेशा से समाज को बेहतर बनाने कि लिए कुछ करना चाहता था और शुद्ध व पौष्टिक खान-पान हमारे समाज की उन्नति के लिए बहुत जरुरी है। मेरे हिसाब से एक प्रगतिशील कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में खेती बहुत महत्वपूर्ण है। हम माँ भूदेवी की पूजा करते हैं और सभी रूपों में उर्वरता को महत्व देते हैं इसलिए मैंने कृषि में आने का फैसला किया। हम सभी की पता है कि आधुनिक खेती में बहुत सारे कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है इसलिए हमने जैविक रूप से स्वस्थ सब्जियाँ उगाने का फैसला किया। रक्षा और कॉर्पोरेट में मेरे अनुभव के साथ, हमें लगा कि पारंपरिक खेती को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर बनाया जाना चाहिए। हम कृषि को देखने के तरीके को बदलना चाहते है। देहरादून में मैं जैविक खेती का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें केसर के साथ शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मूली, प्याज, टमाटर, मिर्च और नींबू जैसी सब्जियाँ उगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम केसर कि बात करें तो केसर एक अत्यधिक मूल्यवान, बेहतर गुणवत्ता वाला मसाला है जिसमें अद्भुत स्वास्थ्य लाभ हैं। इसकी मांग बहुत अधिक है लेकिन आपूर्ति सीमित है मुख्य रूप से कश्मीर से। मुझे याद है कि बचपन में हमारी माँ खीर में और दूध में केसर डालती थी. मगर आज केसर बहुत कम घरों में पाया जाता है। मैं चाहता हूँ कि पहले की भांति केसर हर घर में वापस आए। मेरे जैसे कई लोग इन-डोर केसर खेती के साथ प्रयोग कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम अगले कुछ वर्षों में भारत में केसर का उत्पादन बढ़ाएंगे। वैज्ञानिक तरीकों और नियंत्रित वातावरण के साथ हम पूरे देश में केसर का उत्पादन कर सकते हैं जिससे यह फिर से एक घरेलू मसाला बन जाएगा। अधिक लोग इसके औषधीय गुणों से लाभ उठाएंगे और स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम होंगे।

अगर आप भारतीय नौसेना में ना गए होते तो क्या पूर्णकालिक खेती को अपना करियर चुनते?

जब मैं युवा था तब मैंने खेती को एक करियर के रूप में कभी नहीं सोचा था लेकिन आज शिक्षा और वित्तीय स्थिरता के साथ मैं खेती को अलग तरह से देखता हूँ। मेरे पास प्रयोग करने का समय है और यह एक शांतिपूर्ण, संतोषजनक गतिविधि बन गई है। शहर के शोर से दूर, भूमि पर काम करना शांतिदायक है। अपनी शिक्षा, अनुभव और आधुनिक तकनीक के साथ मैं भूमि का आर्थिक रूप से उपयोग कर रहा हूँ जिससे मेरे और मेरे साथ जुड़े लोगों के परिवार को लाभ होगा। अब मैने खेती को एक पूर्णकालिक करियर के रूप में देखना शुरू कर दिया है। सरकारी समर्थन, बैंकिंग और आधुनिक खेती के तरीकों के साथ मैं जैविक भोजन को व्यावसायिक रूप पर उगाने की दिशा में कार्य कर रहा हूँ।

आप देहरादून में लैब आधारित केसर उगा रहे हैं। इसकी खेती कैसे की जाती हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएं।

हाँ, यह बिल्कुल सही है। हम अब देहरादून में केसर उगा रहे हैं। पारंपरिक रूप से केसर कश्मीर (जैसे पम्पोरे और किश्तवार क्षेत्रों) में उगाया जाता है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में इसे उगाने के प्रयोग किए हैं जिन पर अभी भी शोध चल रहा है। निजी व्यक्ति भी इन-डोर प्रयोगशालाओं में केसर उगाने के प्रयोग कर रहे हैं जहाँ वे तापमान, प्रकाश

और नमी को नियंत्रण में रखने कि लिए इंसुलेटेड चैंबर के प्रयोग कर रहे हैं जो कश्मीर के वातावरण की नकल करते हैं। ये प्रयोग वैश्विक स्तर पर सफल रहे हैं और भारत में भी इसकी प्रगति हो रही है। दूसरों के अनुभव से सीखते हुए हमने देहरादून में पिछले साल शुरुआत की और एक साइकिल पूरा कर चुके हैं। हम इस साल प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं और बेहतर फसल की उम्मीद कर रहे हैं। अगले साल जब हमारी तीसरी फसल होगी हमें लगता है कि हम ब्रेक-इवन पर पहुँच जाएंगे और सर्वोत्तम मसाला प्रदान करेंगे। सीखने की यह प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं है। थोड़ी लगन, मेहनत और पढाई से यह की जा सकती है। इसमें थोड़े वित्तीय निवेश की आवश्यकता भी है। अगर लोग चाहे तो अपने घर कि छत्त पर छोटे रूप में इसके शुरुआत कर सकते है। अधिक से अधिक लोगों के शामिल होने से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता वाले केसर प्रदान कर सकते हैं।

केसर को लेकर भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं?

अगले साल 2027 के अंत तक हमें केसर उगाने के विषय पर काफी अनुभव और ज्ञान हो जाएगा और उम्मीद है हम पर्याप्त लाभ भी कमाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम केसर के उत्पादन को बढ़ाते रहे। हम लोगों को उनकी अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित करने में मदद करना चाहते है। हम उन्हें प्रशिक्षित करेंगे, अपने ज्ञान को साझा करेंगे और उन्हें निवेश करने और गलतियों से बचने के तरीके सिखाएंगे। हम उन्हें फसल प्राप्त करने, अपने उत्पादों का विपणन करने और धन बनाने में मदद करेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। केसर बहुत श्रम-गहन नहीं है। श्रम की आवश्यकता केवल 2-3 बार होती है। इसे भूमि और स्थान की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है और उत्तराखंड में उपयुक्त तापमान है। न्यूनतम तकनीक के साथ हम रोजगार पैदा कर सकते हैं। उत्तराखंड और अन्य पहाड़ी राज्यों में समृद्धि और स्वास्थ्य ला सकते हैं। लोग केसर उगाने में अपना समय, ऊर्जा और रुचि लगा सकते हैं जिससे क्षेत्र को लाभ होगा।

पैसे की समझः हर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जरूरी वित्तीय ज्ञान

डॉ. राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

MBBS, DCh, MD -Radiodiagnosis
Professor of Radiodiagnosis
(SGRR Institute of Medical & Health Sciences, Dehradun)

भारत का मध्यम वर्ग देश की आर्थिक रीढ़ माना जाता है। यह वर्ग मेहनती है, जिम्मेदार है और अपने परिवार के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। महीने की सैलरी आती है, घर का खर्च चलता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन फिर भी अक्सर एक ही सवाल मन में उठता है- "इतनी मेहनत के बाद भी पैसा क्यों नहीं बचता?"

यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की है और इसका कारण कमाई कम होना नहीं है बल्कि पैसे को सही तरीके से मैनेज न कर पाना है। बिना योजना के खर्च, बिना लक्ष्य के बचत और बिना समझ के निवेश-यही वह चक्र है जिसमें अधिकतर लोग फंसे रहते हैं। पैसा तभी सही तरीके से काम करता है जब उसे एक स्पष्ट दिशा दी जाए। अगर आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो आप चाहे जितना भी बचत या निवेश करें, उसका कोई ठोस परिणाम नहीं मिलेगा। हम में से अधिकांश लोग यह मानते हैं कि हम बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। रोजमर्रा के छोटे-छोटे खर्च धीरे-धीरे बड़ी रकम में बदल जाते हैं। जीवन में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। ऐसे समय में बचत ही आपका सहारा बनती है। यदि आपके पास 5-6 महीने के खर्च के बराबर राशि सुरक्षित है, तो आप कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। सिर्फ बचत करने से पैसा सुरक्षित तो रह सकता है लेकिन वह बढ़ता नहीं है। महंगाई धीरे-धीरे आपकी बचत की वास्तविक कीमत को कम करती रहती है इसलिए निवेश करना आवश्यक हो जाता है। निवेश का मतलब जोखिम उठाना नहीं है बल्कि समझदारी से जोखिम को नियंत्रित करना है। सही म्यूच्यूअल फण्ड में SIP जैसे साधनों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति छोटी-छोटी राशि से निवेश शुरू कर सकता है। बीमा का उद्देश्य केवल सुरक्षा प्रदान करना है। टर्म इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा हर परिवार के लिए जरूरी हैं। व्यक्तिगत वित्त किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करता। यह एक संतुलन है-लक्ष्य, बजट, बचत, निवेश और सुरक्षा के बीच। मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक सफलता कोई जटिल विषय नहीं है। यह छोटे-छोटे सही निर्णयों और अनुशासन का परिणाम है।

"पैसे को कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे समझना और सही दिशा देना ही असली समझदारी है"

(लेखक फाइनेंस एडवाइजर एवं एएमएफआई रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं)

धामी ने 'श्रमिक सेवा' ऐप लॉन्च कर 8005 श्रमिकों को DBT से दिए 17 करोड़ रुपए

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विकसित श्रमिक सेवा मोबाइल एप का लोकापर्ण करने के साथ ही 8005 श्रमिकों के खाते में 17 करोड़ से अधिक राशि का डीबीटी के माध्यम से हस्तातंरण किया। मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बोर्ड को अधिक से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि, अनुदान वितरण में पारदर्शिता बरते जाने के क्रम में ऑफलाईन अनुदान वितरण बन्द कर ऑनलाईन निस्तारण एवं डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में धनराशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के जरिए अब तक 11828 लाभार्थियों को कुल 29.89 करोड़ की धनराशि वितरित की जा चुकी है। आज 8005 लाभार्थियों को कुल 17.25 करोड़ की धनराशि वितरित की जा रही है। इस प्रकार विगत 06 माह में अब तक कुल 19833 लाभार्थियों को 47.14 करोड़ की धनराशि वितरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाए, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए स्थानीय श्रमिकों को पलम्बर, इलैक्ट्रिशियन, मिस्त्री, कारपेन्टर आदि क्षेत्रों में कौशल प्रदान किया जाए। इसी तरह योगा एंव वेलनेस में रोजगार की सम्भावना को देखते हुए आगामी सत्र में श्रमिकों के बच्चों को योग एवं वेलनेस में नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को कौशल प्रशिक्षण उपरान्त विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास करे। इसके लिए विदेश मंत्रालय भारत सरकार में पंजीकृत एजेन्सी के माध्यम कार्यवाही की जाए। साथ ही श्रमिकों को पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ने और उनका समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण पर भी ध्यान दिया जाए। इस हेतू श्रमिकों के कार्य स्थल पर ही चिकित्सा परीक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि उनके रोजगार में व्यवधान उपलब्ध न हो। इस मौके पर श्रमायुक्त श्री पीसी दुम्का ने बताया कि न्नस्ब्ब्डै च्वतजंस पोर्टल के माध्यम से अब तक 16000 अधिष्ठानों का पंजीकरण हो चुका है, जिसके जरिए शुल्क के रूप में 80,00000.00 (रूपये अस्सी लाख मात्र) धनराशि जमा हो चुकी है, साथ ही बोर्ड के पास अब तक कुल 324 करोड़ की धनराशि सेस के रूप में जमा हो चुकी है। जिसे श्रमिकों के कल्याण में उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिकों के बीच सामग्री वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। जिससे लाभार्थियों का लाईव फोटो एवं जियो ट्रेकिंग द्वारा सामग्री वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। इस मौके पर उपायुक्त विपिन कुमार सहित बोर्ड के अन्य अधिकारी उपस्थित हुए।

उत्तराखण्ड में जनगणना- 2027 का शुभारंभ

उत्तराखण्ड में जनगणना-2027 की प्रक्रिया का शुभारंभ आज 10 अप्रैल 2026 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) द्वारा लोक भवन में स्व-गणना के माध्यम से किया गया। इसके साथ ही प्रदेश में जनगणना के प्रथम चरण की गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई हैं। यह जनगण ना भारत की पहली पूर्णत: डिजिटल जनगणना है, जिसमें डेटा संग्रहण डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही, नागरिकों को स्व-गणना की सुविधा प्रदान की गई है, जो एक सुरक्षित एवं वेब-आधारित प्रणाली है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें और स्व-गणना के माध्यम से सटीक एवं पूर्ण जानकारी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि यह वेब पोर्टल आसान और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, जिसमें आम आदमी भी बिना परेशानी के सभी सूचनाएं भर सकता है। राज्यपाल ने युवाओं एवं सामाजिक संस्थाओं से भी आग्रह किया कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें और अन्य लोगों को डिजिटल माध्यमों के उपयोग में सहायता प्रदान करें, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया से वंचित न रहे। जनगणना कार्य निदेशालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की निदेशक श्रीमती इवा आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि उत्तराखण्ड में प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 25 अप्रैल से 24 मई, 2026 तक, 30 दिनों की अवधि में पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा। घर-घर सर्वेक्षण से पूर्व प्रदेशवासियों को 10 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2026 तक स्व-गणना की सुविधा प्रदान की गई है। इस अवधि में नागरिक se.census.gov.in पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर एवं आवश्यक विवरण के माध्यम से लॉग इन कर स्वयं एवं अपने परिवार की जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज कर सकते हैं। इस अवसर पर सचिव श्री दीपक कुमार भी मौजूद रहे।

यमुना मंदिर (खरसाली)
यमुनोत्री का शीतकालीन निवास
गंगा मंदिर (मुखबा)
गंगोत्री का शीतकालीन निवास
ओंकारेश्वर मंदिर (ऊखीमठ)
केदारनाथ का शीतकालीन निवास
नरसिंह मंदिर (जोशीमठ)
बद्रीनाथ का शीतकालीन निवास
सुलभ मार्ग, दिव्य दर्शन—
सर्दियों में भी चारधाम का आशीर्वाद
पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड
नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री
विंटर वंडरलैंड – बर्फ से ढ़के पहाड़ों की गोद में एक यादगार सफ़र
प्रकृति की पवित्र पहचान—
GI टैग वाले उत्तराखंडी उत्पाद
उत्तराखंड के GI-टैग वाले उत्पादों की सूची -
तेजपात
बेरीनाग चाय
मंडुआ
गहत
बुरांस का शरबत
सफेद राजमा
झंगोरा
काला भट्ट
पहाड़ी तोर
लखौरी मिर्च (अल्मोड़ा)
रामगढ़ आडू
लाल चावल (पुरोला)
माल्टा
बिच्छूआ
हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद
ऐपण कला
रिंगाल शिल्प
टम्टा
थुलमा
भोटिया दान
लिखाई लकड़ी की नक्काशी
नैनीताल मोमबत्ती
कुमाऊँनी रंगीन पिछौड़ा
रम्माण मुखौटा
परिवार-सा अपनापन और पहाड़ों सा सुकून-उत्तराखण्ड होमस्टे
मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से आग्रह
सिंगल-यूज़ प्लास्टिक से बचें
यातायात नियमों का पालन करें
वोकल फॉर लोकल
तीर्थ स्थलों की पवित्रता का सम्मान करें
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी | www.uttarainformation.gov.in | DIPR_UK | UttarakhandDIPR | UttarakhandDIPR

दूरदर्शी नीतियां बन रही आधार
विकास की ओर अग्रसर उत्तराखंड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड की हाल में शुरू की गई पहलें समग्र विकास के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। यह जहां एक ओर राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान दे रही है, वहीं उत्तराखंड को प्रगति और परिवर्तन की राह पर तेजी से आगे बढ़ा रही हैं।

राज्य के स्थानीय लोगों से बात करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

नियुक्ति पत्र वितरित करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

" 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड, इन दोनों ही स्तंभों को लगातार मजबूत कर रहा है। ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। "

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

" प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। तीर्थाटन एवं पर्यटन की दृष्टि से लोग यहां आयें, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं ताकि पर्यटक शीतकाल में पर्यटन के साथ तीर्थों का भी आनन्द ले सकें। "

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

सुशासन से सामाजिक समानता और व्यापक कल्याण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए उत्तराखंड में सुधारों की निरंतर धारा प्रवाहित कर रहे हैं। राज्य सरकार उत्तराखंड को समानता, पारदर्शिता और अवसरों की भूमि बनाने की दिशा में [illegible]

समान नागरिक संहिता: व्यक्तिगत कानूनों का एकीकरण

[illegible]

एंटी-चीटिंग कानून: निष्पक्ष परीक्षाओं की गारंटी

[illegible]

महिलाओं को 30% आरक्षण: सशक्तिकरण की दिशा में कदम

[illegible]

ये सुधार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साझा दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जिसमें प्रगतिशील, सशक्त और सक्षम उत्तराखंड के निर्माण की झलक दिखती है, जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है, सुशासन को आधार बनाते हुए अपनी परंपराओं का भी सम्मान करता है। समान नागरिक संहिता (UCC) सुधार सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर नागरिकों के व्यापक कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। निरंतर प्रयासों से राज्य में न्यायपूर्ण और संतुलित वातावरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जनसांख्यिकी की रक्षा: जबरदस्ती धर्मांतरण पर रोक

उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018, संशोधित 2022 व 2024। [illegible]

भूमि कानून 2025: पर्यावरण और धरोहर की सुरक्षा

[illegible]

श्रीअन्न से समृद्धि की ओर
कृषि में आई नई क्रांति

'मंडुआ' की कीमतें बढ़ाने से लेकर विदेशी फलों की खेती को बढ़ावा देने तक राज्य की नीतियां किसानों को सशक्त बना रही हैं और ग्रामीण समृद्धि को सुनिश्चित कर रही हैं।

[illegible]

आईटी और डिजिटल तकनीक आधारित सेवाओं की शुरुआत

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का नया रोडमैप तैयार

नीतिगत सुधारों, वित्तीय प्रोत्साहनों और संस्थागत सहयोग के साथ उत्तराखंड सरकार इनके लिए मजबूत इकोलॉजी तैयार कर रही है।

[illegible]

राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़

[illegible]

नीतिगत प्रोत्साहन और कार्ययोजना

[illegible]

समावेशी और टिकाऊ विकास

[illegible]

संस्थागत सहयोग की मजबूती

[illegible]

विपणन और वैश्विक पहुंच

[illegible]

वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी

नई एमएसएमई नीति के अंतर्गत उद्यमों को ये वित्तीय लाभ प्रदान किए जा रहे हैं:

- श्रेणी के आधार पर 100% तक स्टाम्प ड्यूटी की वापसी
- संयंत्र और मशीनरी पर 50% तक की पूंजी सब्सिडी
- प्राथमिक श्रेणी के लिए 10 लाख रुपये तक की अतिरिक्त पूंजी निवेश सब्सिडी
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग उद्यमियों को 5% अतिरिक्त सब्सिडी
- श्रेणी के अनुसार 21 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी वापसी
- 500 किलोवाट तक के स्वीकृत लोड वाले नए उद्यमों के लिए पांच वर्षों तक बिजली शुल्क की वापसी
- जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेडईडी) सर्टिफिकेशन के लिए मानदेय
- स्वर्ण, रजत और कांस्य श्रेणी में प्रमाणित इकाइयों को 75,000 रुपये प्रति इकाई नकद पुरस्कार

पर्यटन और रोजगार को बल

[illegible]

धामी सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को मिला विस्तार

[illegible]

[illegible]

A MEDIA SOLUTION INITIATIVE

विकसित भारत सशक्त उत्तराखण्ड

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

उत्तराखण्ड के जैविक उत्पाद अब दुनिया की पहली पसंद

हाउस ऑफ हिमालयाज से मिला स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विज़न से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के उत्तम उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही, उनके विपणन के लिए कई पहल भी शुरू की गई है। 'हाउस ऑफ हिमालयाज' की शुरुआत इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत उत्तराखण्ड के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को देश और दुनिया के बाजारों के अनुरूप तैयार किया गया है। ये उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्र के उत्पादों का एक प्रमुख ब्रांड बनकर उभरे हैं।

हाउस ऑफ हिमालयाज इसलिए है खास

एक जिला-दो उत्पाद योजना के साथ दुनिया को लुभा रहे उत्तराखण्ड के उत्पाद

जिला	उत्पाद-1	उत्पाद-2
अल्मोड़ा	बाल मिठाई	ट्वीड
बागेश्वर	ताम्र शिल्प उत्पाद	कीवी के उत्पाद
चमोली	गुलाब जल	हथकरघा के उत्पाद
हरिद्वार	शहद	जैगरी
चम्पावत	शहद	लोहे के उत्पाद
देहरादून	बेकरी उत्पाद	मशरूम के उत्पाद
रुद्रप्रयाग	चौलाई के उत्पाद	मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प
नैनीताल	ऐपण हस्तशिल्प	फल प्रसंस्करण
पौड़ी	हर्बल मेडिसिन	लकड़ी शिल्प
ऊधम सिंह नगर	मैन्था ऑयल	मूंज घास उत्पाद
उत्तरकाशी	सेब के उत्पाद	लाल चावल
पिथौरागढ़	मुनस्यारी राजमा	ऊनी कालीन
टिहरी	पनीर	टिहरी नथ

लोकल से ग्लोबल की ओर उत्तराखण्ड के शिल्प और जैविक उत्पाद

पर्यटक अपने यात्रा व्यय का 5% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करें: प्रधानमंत्री

देवभूमि के पारंपरिक उत्पाद विशिष्ट जीआई टैग से सम्मानित

उत्तराखण्ड का भोटिया दन

उत्तराखण्ड थुलमा

जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) शिल्प उत्पाद

भौगोलिक संकेत (जीआई) उन उत्पादों पर प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है तथा उनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है। दूसरे शब्दों में, यह एक प्रमाणीकरण है, जो किसी उत्पाद को किसी विशेष क्षेत्र से उत्पन्न होने की पहचान कराता है, जहां उत्पाद की दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषता अनिवार्य रूप से उसकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण होती है।

उत्तराखण्ड के निम्नलिखित शिल्प उत्पादों को भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है

उत्तराखण्ड बिच्छू बूटी

उत्तराखण्ड लिखाई (लकड़ी की नक्काशी)

नैनीताल मोमबत्तियां (मोमबत्ती)

उत्तराखण्ड रिंगाल शिल्प

कुमाऊं की रंगवाली पिछोड़ा

उत्तराखण्ड ऐपण

चमोली लकड़ी का रम्माण मुखौटा

उत्तराखण्ड ताम्र उत्पाद

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी | www.uttarainformation.gov.in | DIPR_UK | UttarakhandDIPR | UttarakhandDIPR

विकसित भारत, सशक्त
उत्तराखण्ड
विकास भी विरासत भी
संकल्प से शिखर तक
21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखण्ड, इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। ये दशक उत्तराखण्ड का दशक है।
नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड सर्वांगीण विकास की नई मिसाल बन रहा है। स्थानीय उत्पाद, बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योग एवं निवेश तथा हर मौसम पर्यटन सहित देवभूमि अपनी अलौकिक विरासत को संजोते हुए विकास के नए आयाम छू रही है।
पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड
इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी
केदारनाथ-हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना
दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड निर्माण
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रगति पर
टनकपुर-बागेश्वर रेल सर्वे स्वीकृत
सौंग व जमरानी बांध परियोजना
पर्वतीय जिलों में हेली सेवा विस्तार
अर्थव्यवस्था, निवेश एवं उद्योग
₹3.56 लाख करोड़ निवेश समझौते
₹1 लाख करोड़+ ग्राउंडिंग
अर्थव्यवस्था 26 गुना वृद्धि
₹1 लाख करोड़+ वार्षिक बजट
खुरपिया में स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप
हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड
हरित ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास
1 गीगावाट+ सौर ऊर्जा क्षमता
42,000+ सोलर रूफटॉप
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (सीमांत गांव विकास)
महक क्रांति व मिलेट्स मिशन
धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर
केदारनाथ-बदरीनाथ मास्टर प्लान
मानसखण्ड मंदिर माला मिशन
शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ
83 हिमालयी चोटियाँ पर्वतारोहण हेतु खुलीं
संस्कृत ग्राम पहल
संस्कृति एवं आध्यात्मिक शिक्षा
गीता अध्ययन पाठ्यक्रम में शामिल
दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केन्द्र
स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन (गढ़वाल-कुमाऊं)
बड़े निर्णय
समान नागरिक संहिता लागू
सख्त भू-कानून
सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून
नकल विरोधी कानून
अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण
सुशासन
'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान
28,000+ युवाओं को सरकारी नौकरी
950+ सेवाएं ऑनलाइन (अपुणि सरकार पोर्टल)
12,000 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त
पेंशन योजनाओं में वृद्धि एवं मासिक भुगतान
नेशनल लेवल रैंकिंग व प्रोत्साहन
निर्यात तैयारी सूचकांक में प्रथम (छोटे राज्य)
एसडीजी इंडेक्स में शीर्ष स्थान
स्टार्टअप रैंकिंग में 'लीडर'
खनन सुधारों में देश में दूसरा स्थान
शहरी सुधारों हेतु ₹264.5 करोड़ प्रोत्साहन
नीतिगत सुधार
नई फिल्म नीति (50% तक सब्सिडी)
मिलेट्स नीति (₹134 करोड़ कार्ययोजना)
कीवी नीति (70% अनुदान)
ड्रैगन फ्रूट प्रोत्साहन योजना
महक क्रांति 2026-36
महिला स्वरोजगार एवं लखपति दीदी योजना
लखपति दीदी योजना
प्रधानमंत्री जी के नौ आग्रह
स्थानीय लोगों से: बोली-भाषा का संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छ जल, गांव से जुड़ाव, तिवारी वाले घरों को संवारें
पर्यटकों से: प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें, वोकल फॉर लोकल, यातायात के नियम अपनाएं, तीर्थों की मर्यादा का पालन करें।
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी | www.uttarainformation.gov.in | DIPR_UK | UttarakhandDIPR | UttarakhandDIPR

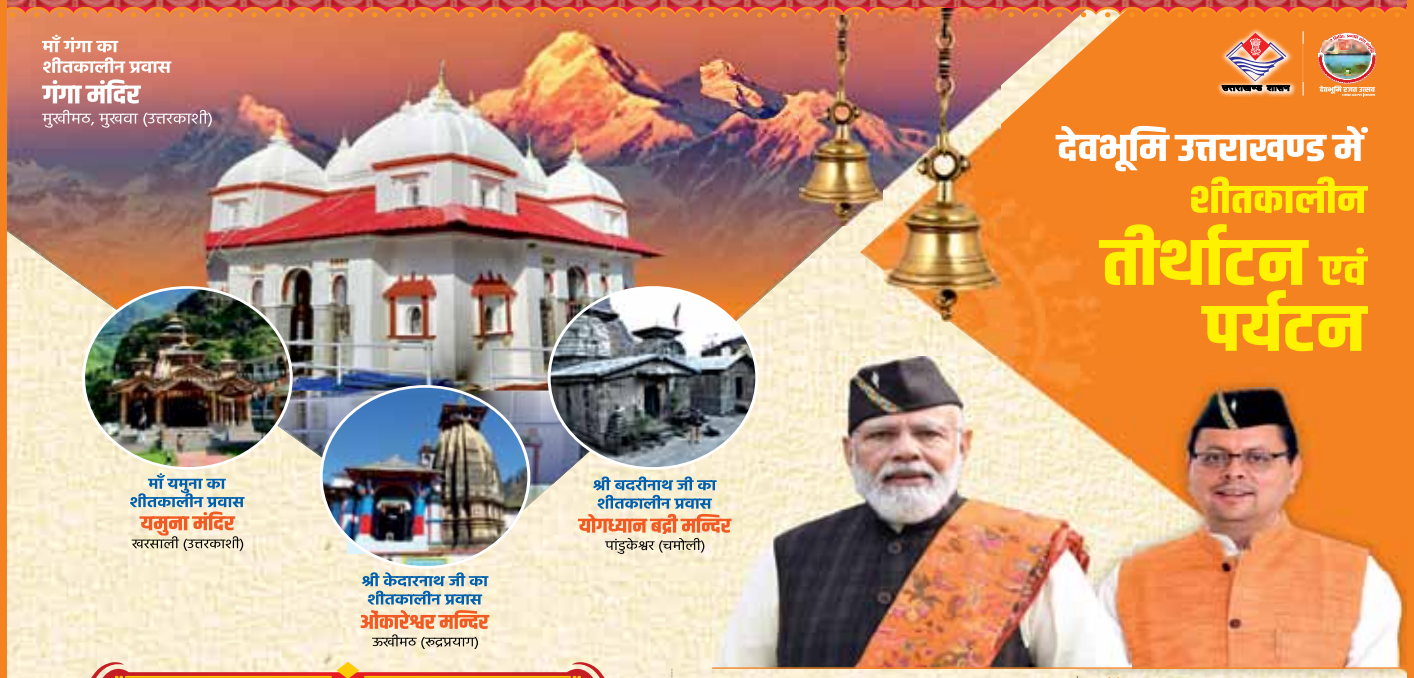

देवभूमि उत्तराखण्ड में शीतकालीन तीर्थाटन एवं पर्यटन

> 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखण्ड इन दोनों ही स्तंभों को लगातार मजबूत कर रहा है। ये दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा।
>
> **नरेन्द्र मोदी**
> प्रधानमंत्री

> प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखण्ड निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। तीर्थाटन एवं पर्यटन की दृष्टि से लोग यहां आयें, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं ताकि पर्यटक शीतकाल में पर्यटन के साथ तीर्थों का भी आनन्द ले सकें।
>
> **पुष्कर सिंह धामी**
> मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

लोकल से ग्लोबल की ओर

उत्तराखण्ड के शिल्प और जैविक उत्पाद

प्रकृति की पवित्र पहचान— GI टैग वाले उत्तराखंडी उत्पाद

उत्तराखंड के GI-टैग वाले उत्पादों की सूची -

- तेजपात
- बेरीनाग चाय
- मंडुआ
- गहत
- बुरांस का शरबत
- सफ़ेद राजमा
- लीची (रामनगर)
- झंगोरा
- काला भट्ट
- पहाड़ी तोर
- लखौरी मिर्च (अल्मोड़ा)
- रामगढ़ आड़ू
- लाल चावल (पुरोला)
- माल्टा
- बिछुआ

रेलमार्ग, राजमार्ग और हवाई मार्ग के क्षेत्र में निरन्तर विकास से अर्थव्यवस्था को मिल रहा बल

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना: ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच 125 किलोमीटर की ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन राज्य के परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मील का पत्थर है। यह परियोजना तीर्थ स्थलों तक आरामदायक पहुंच को सक्षम बनाने, नए व्यापारिक केंद्रों को जोड़ने और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक ठोस पहल है। देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली से होकर गुज़रने वाली यह रेलवे लाइन देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगी।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे: 210 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा की अवधि को मौजूदा 5 घंटे से घटाकर 2.5 घंटे कर देगा। यह छह लेन वाला राजमार्ग है, जिसे आठ लेन तक विस्तारित किया जाना है। यह न केवल यातायात की भीड़ को कम करेगा, बल्कि यह आवासीय और रिटेल विस्तार को भी बढ़ावा देगा। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का एक अनोखा पक्ष इसका वाइल्ड लाइफ़ कॉरिडोर है, जो स्थानीय जीवों को बचाने के लिए विकसित किया गया है और यह 12 किमी लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर है।

हवाई संपर्क: उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत शुरू की गई देहरादून-पिथौरागढ़ उड़ान सेवा ने दोनों शहरों के बीच यात्रा की अवधि को सड़क मार्ग से 12-15 घंटे से घटाकर हवाई मार्ग से केवल 60 मिनट कर दिया है। इस सेवा से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों के बीच संपर्क में सुधार हुआ है, जिससे पर्यटन और वित्तीय गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है।

रोपवे नेटवर्क: केंद्र सरकार ने गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे के निर्माण को मंज़ूरी दी है। इसके अलावा पूर्णागिरी मंदिर रोपवे और काठगोदाम से हनुमानगढ़ी रोपवे परियोजनाएं भी निर्माणाधीन हैं।

होम स्टे से ग्रामीण पर्यटन को लग रहे पंख

योजना के तहत राज्य में अब तक 5703 से अधिक होम स्टे पंजीकृत

पं. दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) योजना अपने आप में सफलता की एक नई कहानी है। जो उत्तराखण्ड में ग्रामीण पर्यटन को एक नई पहचान दे रही है।

योजना का मकसद देशी विदेशी पर्यटकों को उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षित करते हुए, उन्हें उत्तराखण्ड की समृद्ध संस्कृति, खान पान से परिचित कराने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी को मजबूत करना है। योजना के तहत राज्य में अब तक 5703 से अधिक होम स्टे पंजीकृत हो चुके हैं।

इसके साथ ही सरकार वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत वाहन मद और पर्यटन इकाई निर्माण के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। जिसमें अब तक 7300 से अधिक लोगों को लाभांवित किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड पर्यटन प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व का अभूत मिश्रण है। यहां हिमालय की गोद में बसे प्रसिद्ध स्थल सैलानियों को आकर्षित करते हैं। ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग और वन्यजीव अभ्यारण्य भी रोमांच प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं।

उत्तराखण्ड: एक अद्वितीय, रोमांचक व प्राकृतिक गंतव्य

इको-टूरिज्म हो या वाइल्डलाइफ टूरिज्म या रोमांचकारी अनदेखी बर्फीली चोटियां और रोमांचकारी स्कीइंग और माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाडिंग और ट्रेकिंग के रोमांचकारी रास्ते, आपको यहां वह सब कुछ मिल सकता है जिसके लिए कई देशों की यात्रा करनी पड़ सकती है। उत्तराखण्ड अब हरित पर्यटन, माइंडफुल ट्रैवल, वन्यजीव यात्रा, प्राकृतिक पर्यटन के लिए जाना जाता है। बेहतर पर्यटन नीतियों और उच्च संभावनाओं को देखते हुए विगत वर्षों में राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर निवेश तो हुआ ही है साथ ही भविष्य में कई बड़े निवेशकों ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाशी हैं। साहसिक गतिविधियों के लिए उत्तराखण्ड उभरता हुआ पर्यटन स्थल बनता जा रहा है।

पर्यटक अपने यात्रा व्यय का 5% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करें: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वोकल फॉर लोकल की बात कही है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार ने इस योजना को 'वन डिस्ट्रिक्ट-टू प्रोडक्ट' के रूप में आगे बढ़ाया है। बदरीनाथ धाम के निकट माणा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि कहीं भी घूमने जाएं तो अपने यात्रा व्यय का 5 प्रतिशत स्थानीय उत्पादों पर खर्च करें। इससे स्थानीय आर्थिकी में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा। किसी भी क्षेत्र की पहचान उनकी भाषा-बोली एवं स्थानीय उत्पादों से होती है, इनको बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किये जाने चाहिए।

अब सर्दियों में भी लें हिमालयी यात्रा का सुखद आनन्द

औली से लेकर चोपता तक और खिरसू से त्रियुगीनारायण मंदिर तक उत्तराखण्ड में सर्दियों के मौसम में घूमने के लिए कई खूबसूरत और शांत जगहें हैं।

औली: भारत की स्कीइंग राजधानी

बर्फ से ढकी चोटियों और जोशीमठ से चलने वाली विश्वस्तरीय रोपवे के साथ औली रोमांच प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसा है। यहां स्कीइंग, केबल कार राइड्स और सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को बार-बार खींच लाता है।

चोपता: भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड

केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में बसा शांत गांव चोपता, दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ का आधार स्थल है। सर्दियों में यहां की बर्फ से ढकी ट्रैकिंग ट्रेल्स दिव्य और अलौकिक सौंदर्य का अनुभव कराती है।

खिरसू: छिपा हुआ रत्न

पौड़ी गढ़वाल में स्थित अपनी देवदार सुगंधित हवा और 300 हिमालयी चोटियों के विहंगम दृश्य के लिए जाना जाता है। यह एकांतप्रिय यात्रियों और प्रकृति प्रेमी फोटोग्राफरों के लिए आदर्श स्थान है।

कार्तिक स्वामी मंदिर: प्रकृति की अनुपम सुंदरता

रुद्रप्रयाग में 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। सर्दियों में भी यहां तक पहुंचा जा सकता है और चौखंबा पर्वत श्रृंखला के बर्फ से ढके दृश्य मन को मोह लेते हैं।

चौबटिया और रानीखेत: रानी का विश्राम स्थल

सेब के बागों और देवदार के जंगलों से सजा चौबटिया, रानीखेत में सर्दियों में और भी सुंदर हो जाता है। यहां ट्रैकिंग, बर्डवॉचिंग और हेरिटेज वॉक यात्रियों को सुकून भरा अनुभव देती है।

त्रियुगीनारायण मंदिर: प्रेम की शाश्वत ज्वाला

जहां भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था, वह पवित्र स्थान आज एक वैश्विक वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। यहां की अविनाशी ज्वाला सर्दियों की कड़ाके की ठंड में भी निरंतर जलती रहती है। चाहे औली की बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग हो, कार्तिक स्वामी में ध्यान लगाना हो या फिर रानीखेत की शांत गलियों में टहलना, उत्तराखण्ड का हर कोना सर्दियों की ठंड में भी गर्मजोशी से पर्यटकों को दिव्य अनुभूति प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री जी के नौ आग्रह

स्थानीय लोगों से: बोली भाषा का संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छ जल, गांव से जुड़ाव, तिबारी वाले घरों को संवारें

पर्यटकों से: सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बचें, वोकल फॉर लोकल, यातायात के नियम अपनाएं, तीर्थों की मर्यादा का पालन करें

देवभूमि उत्तराखण्ड में आपका स्वागत है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी | www.uttarainformation.gov.in | uttarakhandDIPR | DIPR_UK | uttarakhand DIPR

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027